Shri Govinda Menon: There have been no complaints.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब है ? सवाल कुछ है और जवाब कुछ है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन की तादाद दो हजार कुछ है । श्री ओंकार लाल बेरवा ।

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय किसी भी सवाल का जवाब पूरा नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बुलाता हूं और कोई और साहब बोलने लगते हैं ?

श्री बागड़ी : मैं व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मेरे बिना बुलाये हुए ही आप बोलना शुरू कर देंगे ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : मंत्री महोदय पहले तो जवाब देते ही नहीं हैं फिर जब देते हैं तो उन को यह भी पता नहीं होता कि यहां पर दुकानें कितनी हैं ? तब क्या वह यहां हमारा फोटो लेने आते हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि 2 मार्च, 1966 से जो गेहूं दिया जायेगा वह पूरे राशन के लिये दिया जायेगा या आधा दिया जायेगा अथवा कितना दिया जायेगा ?

Shri C. Subramaniam: For the guests also the same ration is being supplied.

Shri Kashi Ram Gupta: Regarding the supply of wheat, may I know whether sharbati wheat or dara wheat will be supplied?

Shri C. Subramaniam: Whatever quality of wheat is available from Punjab, we shall supply it here. According to Shri Kapur Singh, all wheat from Punjab is good.

Shri Kashi Ram Gupta: Will it be sharbati or dara?

2582(ai)LSD—2.

Mr. Speaker: If Punjab supplies dara wheat, it will be distributed; if Punjab supplies sharbati wheat, it will be distributed. मैं श्री काशी राम गुप्त को बतलाऊं कि पंजाब में सारा गेहूं शरबती व्हीट नहीं होता है । वहां से दड़ा भी आता है और शरबती भी आता है । अगर दिल्ली वालों का सारा शरबती ही मिल जायेगा तो क्या जो लोग पंजाब में रहते हैं वह खाली दड़ा ही खायें ?

Shri Buta Singh: Blackmarketing and smuggling of foodgrains has increased in Delhi after the introduction of the rationing system. Moreover, the citizens of Delhi had to bear an expenditure of Rs. 42 lakhs for the introduction of rationing. In view of all this, do Government still insist on continuing with rationing?

Shri C. Subramaniam: The policy is to continue the rationing system. As far as the expenditure is concerned, Rs. 42 lakhs on a population of 31 lakhs works out to about Rs. 1.2 per head.

Shrimati Savitri Nigam: How far is it correct to say that the Food Ministry in collaboration with the Delhi Administration and the mill-owners has been able to dispose of all the rotten imported wheat which was not being sold, by turning it into atta and distributing it through the ration shops?

Shri C. Subramaniam: These are all wrong allegations. The quality of the wheat is tested and only if it is found fit for human consumption it is issued.

Crop Plan to achieve Targets of Foodgrains

+
*274. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have prepared any crop plan for the forthcoming kharif and 1966-67 rabi season so

as to achieve the targets of agricultural production especially of foodgrains; and

(b) if so, the system of physical directions and incentives that Government intend to employ to achieve the targets?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) No single Crop plan for the entire country for rabi and kharif seasons, has been prepared. But a programme for the cultivation of high yielding varieties of paddy, wheat, maize, jowar and bajra has been drawn up for 1966-67 for an aggregate area of 4.86 million acres.

(b) The programme will be implemented by the State Governments concerned who are being given necessary facilities, advice and assistance particularly in respect of inputs namely seeds, fertilisers and pesticides.

श्री मधु लिमये : पहले तो मेरे प्रश्न का इस में जवाब ही नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, क्या उस के बारे में आप कुछ व्यवस्था करेंगे ? वह राज्यों को क्या मदद दे रहे हैं इस के बारे में कहा गया है। किसान इस योजना को सफल बनायें इसके लिये वह क्या कर रहे हैं पहले वह यह बतलायें तब मैं प्रश्न पूछूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, आप सवाल को देखिए।

"whether Government have prepared any crop plan for the forthcoming kharif and 1966-67 rabi season......"

जो जवाब है वह ठीक यही है :

"No single crop plan for the entire country for rabi and kharif seasons has been prepared...."

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल पूछिए।

श्री मधु लिमये : इधर तीन पांच साला योजना की सरकार ने करीब करीब 2 हजार सफों की किताबें छापी हैं और इनमें दाम नीति के बारे में केवल साधारण और गोल बातें ही हम पाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि, एक ओर ईख, जूट, मूंगफली, सरसों और रुई आदि व्यापारिक फसलें हैं उनके दाम और चावल, गेहूं, ज्वार आदि जो खाद्यान्न हैं उनके दाम, दोनों में बड़ी विषमता पैदा हो गई है, उसके फलस्वरूप हमने देखा कि तीन पांच साला योजनाओं में जहां व्यापारिक फसलों का क्षेत्र 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ा है वहां खाद्यान्न के नीचे जो क्षेत्र है उसमें केवल 17–18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि चौथी पांच साला योजना में और जो यह पहले एक साल की योजना बनेगी उसमें दाम नीति के बारे में कोई विचार किया जायगा ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri C. Subramaniam): I do agree, as far as foodgrains are concerned, the prices were comparatively lower when compared to the commercial crops. Not only that; the agricultural prices, in general, were not in parity with the industrial materials. That is why the Agricultural Prices Commission has been appointed for the purpose of recommending what should be a minimum support price for foodgrains taking into account the non-foodgrain crops and also taking into account the prices of industrial materials.

श्री मधु लिमये : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वह हर एक विकास प्रखंड के लिए और हर एक पंचायती इलाके के लिए फसल की योजना बनायें हर एक पंचायती इलाके में या विकास प्रखंड में कितनी फसल चावल की या गेहूं की या दूसरे खाद्यान्न का पैदा की जाय इसके बारे में कोई योजना बनाई गई है और यह कहा गया है कि अगर इस योजना को सफल नहीं बनाया जायगा तो जो बी० डी० ओ०

या पंचायतों के सरपंच हैं या मुखिया हैं उनको दंडित किया जायगा और सख्त से सख्त सजा उनको दी जायगी ?

Shri C. Subramaniam: I do not think it will be possible to have a regimented pattern of cropping throughout the country. It is the economic factors which will have to function with regard to the prices which we offer to these various producers. It is not as if we are surplus in oilseeds or in cotton. They have also to be grown. Ultimately, the shortages will have to be met only by increasing production per acre.

श्री किशन पटनायक : खाद्यान्न के उत्पादन में जो कमी हो रही है उसका एक बड़ा कारण है कि प्रति एकड़ उत्पादन खासकर के चावल का हिन्दुस्तान में बहुत कम है और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ नहीं सका और दूसरा कारण यह है कि किसान आर्थिक मामले में कमजोर है, अपनी जमीन में ज्यादा पैसा लगा नहीं सकता, इसलिए ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सलाह करके ऐसा कोई उपाय निकालेगी जिसमें कि किसान ज्यादा पैसा अपनी जमीन पर लगा सके ?

Shri C. Subramaniam: Yes, Sir. We are consulting the State Governments for this purpose and we are drawing out plans so that the farmer could get the economic strength to invest more.

श्री विश्वनाथ राय : जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य के सम्बन्ध में फसल योजना जो तैयार की गई है उसको कार्यान्वित करने का भार प्रान्तीय सरकारों के ऊपर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो डेफिसिट एरिया है, कमी वाले क्षेत्र हैं उनके उत्पादन के सम्बन्ध में जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वहां सिंचाई के सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, जहां डेफिसिट है और जहां सम्भावनायें हैं कि पानी अधिक दिया जा सकता है सिंचाई के लिए वहां तत्काल एक एमर्जेंसी योजना बनाई गई है माइनर इर्रीगेशन के लिए और यूटिलाइजशन आफ इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स जो मेजर योजना है उसके लिए भी। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है वहां भी इस साल अधिक रुपया दिया गया है कैश प्रोग्राम में, माइनर इर्रीगशन के लिए और लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए भी अधिक रुपया दिया गया है और जो मेजर इर्रीगेशन है, अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल है, वह कैसे यूटिलाइज किया जाय और उसके लिए भी अधिक रुपया दिया गया है।

श्री तुलशीदास जाधव : कैश क्राप और खाद्यान्न इन दोनों को जो तकावी दी जाती है वह क्या कैश क्राप के लिए ज्यादा दी जाती है और खाद्यान्नों के लिए कम दी जाती है ? यदि हां, तो उससे खाद्यान्न ज्यादा कैसे बढ़ेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र: इस सम्बन्ध में श्रीमन्, इसकी पूरी जांच होती है कि किस क्रप के लिए कितना लोन चाहिए। जो कैश क्रप जैसे टी, कांफी वगैरह उनके लिए पर एकड़ रिक्वायरमेंट आफ लोन ज्यादा होता है और खाद्यान्न में कम होता है और इसी तरह यह दिया जाता है। लेकिन यह सही है कि जिस हद तक यह तकावी दी जानी चाहिए या जिस हद तक कोआपरेटिव क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उसकी कमी है और पैसे की कमी है, सरकार इसको महसूस कर रही है।

Shri Bibhuti Mishra: Has Government given any direction to the Agricultural Prices Commission to give to the growers an integrated remunerative price?

Shri C. Subramaniam: Yes; that is the directive given.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि फूड मिनिस्ट्री कम्यूनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक जगह मर्ज हो गई तो क्या माननीय मंत्री जी डेफिनिट जवाब देंगे कि स्माल इरीगेशन के लिए कितना रुपया डेफिसिट एरियाज में दिया गया है और उनके प्रोग्रेस की क्या आपके पास रिपोर्ट है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं डेफिनिट बता सकता हूं । उत्तर प्रदेश के बारे में डेफिनिट बता दूं जहां के बारे में शिवनारायण जी ज्यादा इन्टरेस्टेड होंगे । वहां अभी हाल में 1 करोड़ रुपया वीयांड प्लान सीलिंग दिया गया है और 50 लाख और दिया गया है, और आशा की जाती है कि 75 लाख और दिया जायगा ।

Shri Tyagi: One crore is nothing.

Shri Surendranath Dwivedy: In reply to the original question the Minister said that there was no preparation of crop planning all over the country. May I know whether this crop planning has been undertaken in any of the States or districts or whether Government of India does not feel the necessity for crop planning at all in this country?

Shri Shyam Dhar Misra: The answer is very clear. No single crop plan for the entire country for rabi and kharif seasons has been prepared. It does not mean that there is no crop planning at all. There is crop planning undertaken in a decentralised way. But there is no single crop plan from the Centre.

Shri P. R. Patel: I want to know whether it is the policy of the Government to have more agricultural production by following a dog-in-the-manger policy, i.e., by allowing the foodgrains to become rotten so that the agriculturists may not get more price and also by having no co-operation with the agriculturists of the country. What is the policy of the Government?

Shri C. Subramaniam: It is certainly not what the hon. Member has said; that it not the policy.

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने फसल योजना के अन्तर्गत खादों को सस्ता करने का भी कोई प्रबन्ध किया है जिससे किसान ज्यादा खाद इस्तेमाल कर सकें ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह बात सही है श्रीमन्, कि जो खाद दी जाती है, फर्टिलाइजर दिया जाता है वह थोड़ा सा और देशों की तुलना में महंगा है लेकिन जिस तरह से गल्ला महंगा हो रहा है उसके अनुसार हिसाब लगाया गया है कि अभी भी इन्सेन्टिव है जो प्राइस खाद की है लेकिन सरकार की यह नीति है खाद को जितना ज्यादा से ज्यादा सस्ता किया जा सके, किया जाय और उस नीति के अनुसार हम अधिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की कोशिश कर रहे हैं और अधिक इम्पोर्ट पूल करके जैसे भी हो सकेगा कोशिश की जायगी ।

Shri Jashvant Mehta: The hon. Minister has said that there is crop planning. The deficit States are suffering from shortage of food due to their producing more of cash crops. Cash crops are also essential for earning foreign exchange. May I know whether Government has given any directive to the State Governments as to what will be the approach of the Government to cash crops and to food crops?

Shri C. Subramaniam: We have a general plan with regard to the targets to be reached in respect of foodgrains, in respect of oilseeds, fibres etc. and they will be kept in mind, we shall take into account the regions in which these things could be grown. It is not the policy of Government that there should be self-sufficiency in respect of each item in each area.